



- III. विकास अधिकारों के हस्तांतरण (TDR) और संयुक्त विकास समझौते में विकास अधिकारों पर जीएसटी लगाने के विभिन्न पहलुओं और उपयुक्त मॉडल की जांच करना;
- IV. कंपोजिशन में भूमि या किसी अन्य घटक को शामिल करने/बाहर करने की वैधता की जांच करना और मूल्यांकन तंत्र का सुझाव देना;
- V. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक किसी भी अन्य पहलू की जांच करना और सुझाव देना, जिसे GoM के संज्ञान में लाया जा सकता है।

3. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित GoM आवश्यकतानुसार केंद्र और राज्यों के अधिकारियों को आमंत्रित कर सकता है। विधि समिति और फिटमेंट समिति के संयोजक GoM की सहायता करेंगे।

4. रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित GoM के सचिव श्री मनीष सिन्हा, संयुक्त सचिव (TRU-II), CBIC होंगे।

5. इसे माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और अध्यक्ष, जीएसटी परिषद के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(धीरज रस्तोगी)  
संयुक्त सचिव, जीएसटी परिषद

प्रतिलिपि:

1. GoM के सभी सदस्य
2. राजस्व सचिव, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष, CBIC, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. विशेष सचिव, जीएसटी परिषद सचिवालय
5. विधि समिति, फिटमेंट समिति और आईटी समिति के संयोजक
6. प्रधान आयुक्त (विंग नीति जीएसटी), CBIC
7. संयुक्त सचिव, TRU-I, राजस्व विभाग
8. संयुक्त सचिव, TRU-II, राजस्व विभाग
9. संयुक्त सचिव, जीएसटी परिषद सचिवालय
10. अध्यक्ष, GSTN
11. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि वे रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए GoM के गठन के संबंध में GST परिषद के माननीय सदस्य को सूचित करें।
12. माननीय राज्य मंत्री (वित्त) के प्रधान सचिव, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. माननीय राज्य मंत्री (वित्त), भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के निजी सचिव